भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3661

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

जम्मू में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना

3661. **श्री जुगल किशोर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) डिजिटल सुविधाओं से लैस किए गए विद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से अनुमोदित किया जाता है। यह सहायता, ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सहित, कक्षा VI से XII तक वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षाओं सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदान की जाती है।

दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अधिगम संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसी डिजिटल शिक्षा पहलों को कार्यान्वित करता है। ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा), स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो क्यूआर-कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी), शिक्षक संसाधन और अन्य अधिगम सामग्री सहित पाठ्यक्रमानुकूल ई-सामग्री प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थी सामग्री डाउनलोड कर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक व्यापक और समतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित होती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को शुरू किया गया पीएम ई-विद्या, देश भर में शिक्षा तक मल्टीमोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा पहलों को एकीकृत करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन पहलों को प्रासंगिक बनाने, इनकी निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं, जबकि एनसीईआरटी निरंतर शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी द्वारा विकसित ई-पाठशाला, अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों (कक्षा I से XII), श्रव्य-दृश्य संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करती है, जिससे शिक्षार्थियों और शिक्षकों को शैक्षिक सामग्री कभी भी और कहीं भी उपलब्ध होती है।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के 711 सरकारी स्कूलों को आईसीटी प्रयोगशालाओं हेतु अनुमोदित किया गया है और इसके अतिरिक्त, 530 स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं हेतु अनुमोदित किया गया है।

सरकार की दीर्घकालिक कार्यनीति, एनईपी, 2020 के आधार पर स्कूली शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। इस दिशा में, समग्र शिक्षा के तहत सरकारी माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और विज्ञान प्रयोगशालाओं की संतृप्ति का कार्य किया गया है।

*****